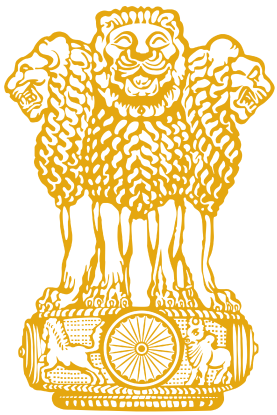

सत्यमेव जयते

पंजाब के राज्यपाल

श्री बनवारीलाल पुरोहित

द्वारा

विधान सभा

में

दिनांक 01 मार्च, 2024 दिन शुक्रवार

को दिया गया

भाषण

माननीय श्री अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण,

1. 16वीं पंजाब विधानसभा के छठे सत्र में इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे जीवंत राज्य पंजाब की यात्रा इसके लोगों की अदम्य भावना से जुड़ी हुई है, जिन्होंने समय-समय पर लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रगति का प्रदर्शन किया है। आज, जब हम इस प्रतिष्ठित सदन में एकत्र हुए हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उन चुनौतियों को स्वीकार करें जो हमारे सामने हैं और एक ऐसे भविष्य की दिशा में एक मार्ग तैयार करें जो समृद्धि, समावेशिता और सतत विकास द्वारा परिभाषित हो।

2. मेरी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक समावेशी विकास के माहौल को बढ़ावा देना है, जहां पंजाब के प्रत्येक नागरिक के लिए आगे बढ़ने और समृद्ध होने के समान अवसर हों। मेरी सरकार विशेषाधिकार प्राप्त और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच की खाई को पाटने का लगातार प्रयास कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मेरी सरकार ने घर-घर मुफ़्त राशन योजना के तहत पंजाब के हर घर तक राशन पहुंचाने की सफलतापूर्वक शुरूआत की है।

3. मेरी सरकार लोकतंत्र, न्याय और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। आइए हम पंजाब के उस भरोसे और विश्वास को ध्यान में रखते हुए, जो उन्होंने हम पर जताया है, लोगों की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करें। यह जानते हुए कि पंजाब का भविष्य हमारे हाथों में है, आइए, हम सब मिलकर साहस और दृढ़ विश्वास के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ें।

4. मेरी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। पूरे पंजाब राज्य में 664 आम आदमी क्लिनिक सफलतापूर्वक कार्यशील हैं। कुल 1.07 करोड़ लोग चिकित्सा उपचार लेने के लिए इन क्लीनिकों में आए हैं। इन क्लीनिकों में मरीजों को प्रचलित बाजार दरों पर 450 करोड़ रुपये की दवाएं और 70 करोड़ रुपये के नैदानिक परीक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। क्लीनिकों ने राज्य के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से होने वाले खर्च को 650 करोड़ रुपये तक की बड़ी राशि कम करने में योगदान दिया है।

5. मेरी सरकार सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को मुफ्त दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की आपूर्ति के लिए 222 करोड़ रुपये की दवाएं खरीदी गई हैं। मेरी सरकार सभी जिला अस्पतालों, उप-विभागीय अस्पतालों और सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

6. मेरी सरकार सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के सुधार की दिशा में प्रयासरत है। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों की इमारतों के अप-ग्रेडेशन के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है।

7. निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकार ने राज्य भर में मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 300 प्रमाणित प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है, जो प्रतिदिन 35,000 नागरिकों को 1500 योग कक्षाओं की सुविधा प्रदान करते हैं।

8. मेरी सरकार ने मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलेरी साइंसेज की स्थापना की है। संस्थान का लक्ष्य क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लीवर और पित्त रोगों के अनुसंधान, निदान और उपचार को आगे बढ़ाना है। कैंसर रोगियों के लिए 114 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में राज्य कैंसर संस्थान और 45 करोड़ रुपये की लागत से फाजिल्का में तृतीयक कैंसर केंद्र का निर्माण किया गया है। इन संस्थानों से नागरिकों को शीघ्र लाभ मिलेगा।

9. मेरी सरकार पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। हम स्कूल स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी काम कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2022 से 9518 शिक्षकों की भर्ती की गई है। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों में निराशा थी क्योंकि वे विभिन्न नियमों और शर्तों पर काम कर रहे थे। इनमें से 12316 योग्य कर्मचारी, जो 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे, उन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ सेवा की गारंटी देने के लिए नियमित किया गया।

10. मेरी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए "पंजाब सिक्खिया क्रांति" शुरू की। । "पंजाब सिक्खिया क्रांति" के तहत हमने 7082 स्कूलों में चारदीवारी बनाने का काम शुरू किया है, इनमें से 1429 स्कूलों में पहली बार चारदीवारी बन रही है। 12126 स्कूलों को इंटरनेट कनेक्शन मिल चुका है। स्कूलों में 4369 शौचालयों की मरम्मत करायी गयी है। इसके अलावा, मेरी सरकार सरकारी स्कूलों को 95,000 डुअल डेस्क उपलब्ध करा रही है।

11. मेरी सरकार 118 सरकारी सीनीयर सैकेंडरी स्कूल को स्कूल आफ़ एमिनेन्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्कूल वैज्ञानिक

शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाओं, पूरी तरह लैस प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों से सुसज्जित होंगे।

12. हमारे स्कूल प्रमुखों को सर्वोत्तम प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुभव से सुसज्जित करने के लिए 198 प्रधानाचार्यों ने प्रिंसिपल अकादमी, सिंगापुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में क्षमता निर्माण के लिए 100 हेड मास्टर्स को भेजा गया।

13. पहल कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को स्कूली छात्रों की वर्दी तैयार करने के लिए लगाया गया है। इस शैक्षणिक वर्ष में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग तीन लाख वर्दियों का निर्माण किया जाएगा।

14. इन सभी प्रयासों से सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लगभग 17% बढ़ गया है।

15. मेरी सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए केंद्रीकृत दाखिला पोर्टल को सफलतापूर्वक लागू किया है। 2023-2024 सत्र के दौरान ही लगभग 1.5 लाख छात्रों ने पारदर्शी तरीके से और बिना किसी परेशानी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इस पोर्टल का लाभ उठाया।

16. मेरी सरकार ने किसानों, विशेषकर सुदूरवर्ती किसानों को नहर का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है, जो वर्षों से नहर के पानी से वंचित थे। इस वर्ष, उस अवधि के दौरान नहर के पानी का उपयोग 38% से अधिक बढ़ गया है जब पानी की अधिकतम मांग थी। यह नहरों की समय पर सफाई और तकनीक की मदद से नहरों की दैनिक निगरानी के कारण संभव हुआ। 400 किलोमीटर की लगभग लंबाई वाली पैंतालीस नहरें, जो बेकार पड़ी थीं, चालू कर दी गईं। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों में पहली बार कंक्रीट बिछाया गया। इसके अलावा, पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से बेकार पड़े 14100 जलस्रोतों को भी बहाल किया गया है। इसके अलावा, 10876 भाईचारक खालों को सरकारी खालों में बदला गया। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि मानसा जिले का सरदूलगढ़ ब्लॉक, जो लंबे समय से हरियाणा से टोहाना हेडवर्क्स के माध्यम से नहर के पानी के अपने वैध अधिकार से वंचित था, मेरी सरकार के प्रयासों के कारण हरियाणा से अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

17. मेरी सरकार द्वारा मनरेगा के तहत धनराशि का उपयोग करके राज्य में 13000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों की सफाई की गई। इससे नहरों की सफाई और री-लाइनिंग के लिए मनरेगा फ़ंड का उपयोग वर्ष 2020-21 में 77 करोड़

रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो 300% से अधिक है।

18. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार के लगातार प्रयासों और निगरानी से, शाहपुरकंडी बांध परियोजना, जो 25 वर्षों से अधिक समय से निष्पादन के लिए लंबित थी, आखिरकार आरंभ होगी। बांध के जलाशय में पानी भरना शुरू कर दिया गया है। इससे राज्य को पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने में मदद मिलेगी। इससे 37,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता भी पैदा होगी और 206 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली बनाने में मदद मिलेगी। यह बांध पर्यटन की नई संभावनाएं भी पैदा करेगा जिस से राज्य के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

19. प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने उत्तरी भारतीय नहर और जल निकासी अधिनियम 1873 को रद्द कर दिया है, जो 150 साल पुराना क़ानून था। अधिनियम के प्रावधान निरर्थक हो गये थे। नए अधिनियम ने किसानों को राहत देते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।

20. मेरी सरकार राज्य में गिरते भूजल स्तर से पूरी तरह से अवगत है। कई जिलों में भूजल चिंताजनक दर से गिर रहा है। इस घटती प्रवृत्ति को रोकने के लिए, नहर के पानी का उपयोग भूजल को रिचार्ज करने के लिए किया जा रहा है और

इस उद्देश्य के लिए केवल एक वर्ष में 129 रिचार्ज स्थलों का निर्माण किया जा चुका है।

21. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष राज्य को अभूतपूर्व बारिश का सामना करना पड़ा, मानसून अवधि के 3 महीनों की पूरी वर्षा केवल 02 दिनों, यानी 9 और 10 जुलाई 2023 को हुई। पर, मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत सभी संभव उपाय किए कि बाढ़ के कारण लोगों, विशेषकर किसानों को कम से कम नुकसान हो। यह पहली बार है कि जुलाई माह में इतनी बाढ़ आयी, जो राज्य के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं आयी थी। हालाँकि, मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बीबीएमबी के साथ लगातार संपर्क में थी कि बांधों से पानी बहुत नियमित तरीके से छोड़ा जाए।

22. मेरी सरकार पंजाब में सभी क्षेत्रों को विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लागू करने के लिए समर्पित रहेंगे।

23. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने बहुत कम लागत पर 540 मेगावाट क्षमता का एक निजी थर्मल प्लांट जीवीके गोइंदवाल साहिब का अधिग्रहण किया है, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने आप में एक इतिहास है।

यह प्लांट 1080 करोड़ रूपए यानी 2 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट की लागत से अधिग्रहण किया गया है जबकि एक नए थर्मल प्लांट की लागत ₹ 8.5 करोड़ प्रति मेगावाट है। अधिग्रहण के बाद इस प्लांट का नाम बदलकर गुरु अमरदास थर्मल प्लांट रख दिया गया है। पंजाब की अपनी पछवारा कोयला खदान से कोयले के उपयोग से इस संयंत्र में उत्पादन दोगुना से भी अधिक बढ़ जाएगा। बिजली खरीद लागत के संदर्भ में प्रति वर्ष लगभग ₹ 350 करोड़ की बचत होगी।

24. इससे पहले पिछली सरकारों के दौरान, सौर ऊर्जा की खरीद के लिए प्रति यूनिट ₹ 4.73 से ₹ 17.91 की दर पर पी.पी.एज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेरी सरकार के नेक इरादों के कारण, हमने 2804 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 2.33 रुपये से 2.76 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 10 पीपीए हासिल किए।

25. राज्य की बंद पड़ी कोयला खदान यानी झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित पछवारा कोयला खदान, जो 7 साल से अधिक समय यानी अप्रैल 2015 से बंद पड़ी थी, दिसंबर-2022 में चालू हो गई। अब तक, राज्य के थर्मल प्लांटों को पछवारा कोयला खदान से लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कोयला यानी 1000 रेलवे रेक प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की कीमत कम होने से 450 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

26. पछवारा से अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले ने संयंत्र प्लांट में सुधार किया है और पीएसपीसीएल थर्मल पावर स्टेशनों को अब बिजली के इष्टतम उत्पादन के लिए कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उन के पास हमेशा 25 दिनों या उससे अधिक समय के लिए कोयले का स्टॉक रहता है। इसके अलावा, पछवारा कोयला खदान से कोयले की उपलब्धता के कारण 2023-24 के दौरान राज्य के थर्मल प्लांटों में किसी भी आयातित कोयले का उपयोग नहीं किया गया, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई।

27. 2023-24 के दौरान पंजाब ने 23.06.2023 को 15,325 मेगावाट की अपनी सर्वकालिक उच्चतम मांग को पूरा किया है। कुल मिलाकर 09.09.2023 को एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 3427 लाख यूनिट ऊर्जा की मांग पूरी की गई।

28. मेरी सरकार ने घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं पर कोई बिजली कटौती किए बिना धान के मौसम के दौरान कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे से अधिक की आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिसके कारण धान की बंपर फसल हुई है।

29. जीवन स्तर में सुधार के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। मेरी सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली

योजना लागू की है। इससे बिलिंग चक्र में शून्य बिल प्राप्त करने वाले लगभग 70 लाख यानी 90% परिवारों को लाभ हुआ है।

30. मेरी सरकार ने नागरिकों को मांग के अनुसार घर बैठे सेवाएं प्रदान करने के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी या "भगवंत मन सरकार तुहाडे द्वार" नाम से एक नई योजना शुरू की है। योजना के तहत, 43 नागरिक सेवाओं की पहचान की गई जो लेनदेन की मात्रा का 99% से अधिक है। अब तक 15,000 से अधिक नागरिकों ने सेवाओं का लाभ उठाया है। इससे उन नागरिकों को राहत मिली है, जिन्हें अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार ने आप की सरकार आप दे द्वार नाम से एक और योजना शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को उनके गांव में सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 8 लाख से अधिक नागरिक पहले ही कैंपों का दौरा कर चुके हैं और अपने निवास स्थान पर सेवाओं की उपलब्धता का लाभ उठा चुके हैं।

31. मेरी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने गंभीर प्रयासों से, मेरी सरकार को लगभग 65,993 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 4242 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस से लगभग 3,20,882 लोगों को रोजगार मिलेगा।

32. हमने उद्योग परियोजनाओं को नियामक मंजूरी तेजी से और सुचारू रूप से जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सेल डीड के पंजीकरण में ग्रीन स्टांप पेपर भी आरंभ किया है।

33. उद्योगों के मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के उद्देश्य से उनके साथ परामर्श करने के लिए विभिन्न शहरों में "सरकार सन्नतकार मिलनी" का आयोजन किया गया। इन बैठकों में कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए जैसे खनन शुल्क की माफी, संपत्ति कर की एकमुश्त निपटान योजना, उद्योग के लिए कंपाउंडिंग नीति में बड़ी राहत और औद्योगिक फोकल प्वाइंट के उन्नयन पर विशेष जोर, साथ ही उद्योग संबंधित बुनियादी ढाँचे पर 1158 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर और आईटी सिटी मोहाली के औद्योगिक क्षेत्रों में दो नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

34. राज्य के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा देने के लिए, एसएएस नगर में 11-13 सितंबर, 2023 तक तीन दिवसीय रंगला पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन और ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। पहले प्रमुख पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन ने दुनिया भर के लोगों को पंजाब के पारंपरिक मूल्यों और समृद्ध संस्कृति से परिचित करवाया। शिखर सम्मेलन में देश भर से भाग लेने वाले निवेशकों को राज्य में निवेश के विभिन्न अवसरों को दर्शाया गया।

35. मेरी सरकार द्वारा पंजाब राज्य में विभिन्न स्मारकों के निर्माण, रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख परियोजनाएं खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास जी का स्मारक, अमृतसर में भगवान वाल्मिकी राम तीर्थ स्थल परिसर में आधुनिक पैनोरमा का विकास, रामपुरा फूल में किले का संरक्षण, विरासत-ए-खालसा का उन्नयन/नवीनीकरण, श्री आनंदपुर साहिब, भाई जैता जी मेमोरियल श्री आनंदपुर साहिब आदि हैं। मेरी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एंग्लो-सिख वॉर सर्किट विकसित करने के लिए 15.50 करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए हैं।

36. मेरी सरकार ने, पिछले एक वर्ष में 1,332 प्लेसमेंट कैम्प/जॉब फेयर/स्वरोजगार कैम्पों के माध्यम से 1,11,810 अभ्यर्थियों को नौकरी/स्वरोजगार की सुविधा दी है। मेरी सरकार ने राज्य में 25 नये सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं। इन नये आईटीआई के खुलने से प्रदेश के लगभग 8000 युवाओं को लाभ मिलेगा।

37. पिछले एक साल के दौरान महाराजा रणजीत सिंह सशस्त्र बल और तैयारी संस्थान, माई भागो सशस्त्र बल और तैयारी संस्थान और पंजाब युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र

(सी-पाइट) द्वारा 6,079 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 288 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई।

38. योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के प्रयास को जारी रखते हुए, मेरी सरकार ने भर्ती में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ दक्षता भी सुनिश्चित की है। इस सरकार द्वारा अब तक सरकार के 40 विभागों में दी गई सरकारी नौकरियों की संख्या 40437 है। अब प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें पंजाब के कई सक्षम युवा जो विदेश जाने का विकल्प चुन रहे थे, अब पंजाब सरकार की सेवा में शामिल हो रहे हैं।

39. ग्रामीण आजीविका को और बेहतर बनाने के अपने प्रयास में, मेरी सरकार ने मनरेगा योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजाब ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1200 करोड़ रुपये की कुल लागत से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रकृति के लगभग 1.64 लाख कार्य किए हैं। इससे 319 लाख से अधिक मानव-दिवस उत्पन्न करने में मदद मिली है, जिससे 8.26 लाख परिवारों को बहुत आवश्यक जीविका प्रदान हुई है। इस योजना के तहत, मेरी सरकार ने विभिन्न गांवों में खेल के मैदान विकसित करने की पहल की है, जो हमारे युवाओं के मनोरंजन और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चालू

वित्तीय वर्ष में अब तक 1560 खेल के मैदान विकसित किये गये हैं तथा 2252 खेल के मैदानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, इस योजना के तहत, पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में राज्य भर में 70 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

40. मेरी सरकार की सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सफल कार्यान्वयन से स्पष्ट है। लक्षित किए गए 39,762 घरों में से 89% पूरा होने के साथ, हम 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सम्मानजनक आवास के अपने वादे को पूरा करने की राह पर अग्रसर हैं।

41. ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध गाँव की सामान्य भूमि, या शामलात भूमि से उत्पन्न राजस्व, ग्राम पंचायतों को गाँव के कल्याण के लिए विकास प्रकृति के कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी संसाधन प्रदान करता है। पर, पिछले कुछ वर्षों में इन सार्वजनिक संपत्तियों के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों के संसाधन कम हो गए हैं। मेरी सरकार ने इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सक्रिय कदम उठाया है और अब तक 3000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 12224 एकड़ से अधिक शामलात भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने में सफल रही है।

42. पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता के प्रति मेरी सरकार के प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

43. मेरी सरकार पंजाब के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अप्रैल 2023 में, पंजाब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया।

44. मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपलब्ध कराया जाने वाला पानी उचित सेवा स्तर के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला हो। हाल के वर्षों में विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे भूवैज्ञानिक संदूषकों से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल के बजाय सतही जल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन सभी जल-गुणवत्ता प्रभावित गांवों (685 संख्या) को, जो सतही जल से कवर नहीं किए जा सके, 125.13 करोड़ रुपये की लागत से आर्सेनिक और लौह निष्कासन प्लांट या सामुदायिक शुद्धिकरण प्लांट प्रदान किए गए हैं।

45. मेरी सरकार ने ब्लू स्टार से प्रभावित धर्मी फौजियों की सहायता हेतु मासिक अनुदान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। युद्ध/संचालन में अपने वास्तविक

आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान विकलांग होने वाले रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों को अनुग्रह राशि उनकी विकलांगता के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।

46. मेरी सरकार ने युद्ध जागीर के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये सालाना कर दी है।

47. मेरी सरकार ने खेल के क्षेत्र में पंजाब के गौरव को बहाल करने के लिए 2023 में राज्य की नई खेल नीति को अधिसूचित किया, जिसके लिए राज्य पहले जाना जाता था लेकिन पिछले कुछ समय में इस में गिरावट आई थी। नई खेल नीति के तहत पहली बार एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित प्रदेश के 58 खिलाड़ियों को तैयारी अनुदान के रूप में 4.59 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई। पहली बार, पंजाब के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 20 पदक जीते, जो 1951 में शुरू हुए एशियाई खेलों के बाद से सबसे अधिक पदक हैं। उन्हें बिना देर किए 29.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। मेरी सरकार ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक जीतने वाले राज्य के 136 खिलाड़ियों को 4.58 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया।

48. 4 दशकों के बाद, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाले राज्य के 9 खिलाड़ियों की उपलब्धि को मान्यता देने के लिए और एक क्रिकेटर और एक एथलीट को मेरी सरकार ने हाल ही में 7 खिलाड़ियों को पीपीएस और 4 को पीसीएस में नियुक्त किया।

49. मेरी सरकार ने खेडां वतन पंजाब दीयां शुरू करने की पहल की थी, जिसमें दूसरे सीज़न में 4.5 लाख बच्चों, युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई, जो पिछले साल 3.5 लाख व्यक्तियों की भागीदारी से अधिक थी। खेडां वतन पंजाब दीयां के सभी आयु वर्ग के 12000 विजेताओं को 8.97 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए।

50. मेरी सरकार ने खेल विभाग में कर्मचारियों की संख्या मौजूदा 350 से बढ़ाकर 2360 करने की मंजूरी दे दी है। इसमें से 500 पद अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। यह राज्य के खिलाड़ियों के लिए जीत की बड़ी प्रेरणा होगी। खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहें यह सुनिश्चित करने के लिए नई खेल नीति के तहत स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक नया कैडर स्थापित किया जाएगा।

51. मेरी सरकार ने प्रदेश में 1000 खेल नर्सरियां खोलने का निर्णय लिया है। यह प्रत्येक ग्रामीण और शहरी परिवार के 4 किमी के भीतर एक खेल सुविधा प्रदान करेगा। जहां खेल नर्सरियां प्रतिदिन 60,000 बच्चों को बुनियादी कोचिंग,

उपकरण और उच्च प्रोटीन आहार प्रदान करके राज्य में एक खेल संस्कृति बनाने में मदद करेंगी, वहीं 1000 अच्छे खिलाड़ियों को कोच के रूप में रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी, इस से युवाओं में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में भी मदद मिलेगी, स्वस्थ वैकल्पिक रास्ते प्रदान करके वे अपना समय और ऊर्जा सार्थक कार्यों में लगा सकते हैं।

52. मेरी सरकार एनआरआई भाईचारे को अपने संबंधित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। एनआरआई उनके द्वारा संचालित किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना पर 50% का योगदान कर सकते हैं, जहां शेष 50% का योगदान राज्य द्वारा किया जाता है।

53. मेरी सरकार ने आदमपुर में 110.00 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक सिविल एयर टर्मिनल के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपये मूल्य की 40 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 41.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो मजबूत विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

54. लुधियाना में इंटरनेशनल सिविल एयर टर्मिनल हलवारा के लिए 135.54 एकड़ भूमि का आवंटन मेरी सरकार के

सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह 44.00 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा होने वाला है जो क्षेत्रीय विमानन बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लिंक सड़कों और बाड़ लगाने जैसे अस्थायी टर्मिनल-संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 50.00 करोड़ रुपये की राशी विमानन को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाते हैं।

55. जैसा कि मेरी सरकार ने वादा किया था, भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभियान तेजी से जारी रहा। पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंजाब ने 16-03-2022 से 08-01-2024 की अवधि के दौरान 23 राजपत्रित अधिकारियों, 193 गैर-राजपत्रित अधिकारियों और 55 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 195 ट्रैप मामले दर्ज किए हैं, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसके अलावा 241 आपराधिक मामले दर्ज किये गये जिनमें 82 राजपत्रित अधिकारी, 269 अराजपत्रित अधिकारी और 300 निजी व्यक्ति शामिल थे।

56. मेरी सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए एक समर्पित सड़क सुरक्खया फ़ोर्स के नाम से देश में अपनी तरह की नई शुरूआत की है। विशेष रूप से प्रशिक्षित नए भर्ती किए गए 1597 कर्मियों को इस बल की रीढ़ की हड्डी के रूप

में कार्य करना है, जिन्हें नवीनतम पूरी तरह से लैस 144 वाहन प्रदान किए गए हैं। यातायात दुर्घटनाओं की आशंका वाले 4200 किमी राजमार्गों पर यह बल तैनात किया गया है। निर्दिष्ट क्षेत्रों में गश्त करने के अलावा, वे यातायात उल्लंघनों के लिए निवारक के रूप में कार्य करते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की भूमिका और जिम्मेदारी निभाते हैं। 1 फरवरी, 2024 को अपने औपचारिक लॉन्च के दस दिनों के भीतर, बल ने आठ मिनट से भी कम समय के रिकॉर्ड प्रतिक्रिया समय के भीतर 25 लोगों को निकटतम अस्पताल पहुंचाने और कई कीमती जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, चौबीसों घंटे तैनाती के परिणामस्वरूप राजमार्गों पर आपराधिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि पहले पुलिस की उपस्थिति नगण्य थी।

57. मेरी सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के जीवन और शारीरिक नुकसान को बचाने के लिए फरिश्ते योजना अधिसूचित की है। दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आम जनता को उनकी परेशानी मुक्त भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी सरकार उनके नेक कार्यों की सराहना करने के लिए 2000/- रुपये का नकद पुरस्कार देगी। नकद पुरस्कार के अलावा, ऐसे व्यक्तियों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें

कानूनी जटिलताओं और पुलिस पूछताछ से छूट प्रदान की जाएगी।

58. पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बेहतर होती जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और पीजीडी पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। एजीटीएफ ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ समर्पित अभियान चलाया है, जिससे कई वांछित गैंगस्टरों और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के साथ-साथ विभिन्न गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। अब तक, एजीटीएफ ने अन्य फील्ड इकाइयों के साथ मिलकर 951 गैंगस्टरों/अपराधियों को गिरफ्तार करने, 14 गैंगस्टरों को ढेर करने, 312 मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने, 963 हथियार और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 208 वाहनों को बरामद करने में सफलता हासिल की है।

59. पंजाब पुलिस ने 16 मार्च, 2022 से 18,953 एफआईआर दर्ज करके 25,385 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और राज्य भर से 1860 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और इसके अलावा, पंजाब पुलिस की टीमों ने गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से 147 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। जिससे

हेरोइन की कुल प्रभावी बरामदगी 2007 किलोग्राम हो गई है। इसके अलावा, पुलिस ने राज्य भर से 1247 किलोग्राम अफीम, 1229 किलोग्राम गांजा, 604 क्विंटल पोस्त भूसी और फार्मा ओपियोइड की 1.12 करोड़ गोलियां/कैप्सूल/इंजेक्शन/शीशियां भी बरामद की हैं। ड्रग तस्करों की 142 करोड़ रुपये की 355 संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त करने की मंजूरी दे दी गई है।

60. अपराध, विशेषकर गैंगस्टर गतिविधियों और नशीली दवाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू की गई। नशीली दवाओं और अपराध के हॉटस्पॉट में 210 से अधिक राज्य स्तरीय कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन (सीएएसओ) चलाए गए।

61. आम आदमी को साइबर अपराध से बचाने के लिए, मेरी सरकार ने डीआईटीएसी लैब, राज्य साइबर अपराध सेल और जिला-स्तरीय साइबर अपराध सेल सहित साइबर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए फ़ंड स्वीकृत किया है। हमारी जेलों को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक जैसे एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, फुल बॉडी स्कैनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

62. पंजाब के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मेरी सरकार पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए नियमित

अभियान चला रही है। मेरी सरकार द्वारा पुलिस शहीदों के परिवारों को समय-समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

63. मेरी सरकार ने नवीनतम न्यायिक वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू कर दिया है। इससे पंजाब राज्य की अदालतों में कार्यरत हजारों न्यायिक अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारियों को लाभ होगा।

64. जनता को खनन माफिया से राहत देने के लिए मेरी सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक खनन स्थल खोले हैं। इन खदानों ने स्थानीय युवाओं और श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया है। अन्यथा ये कमाई ठेकेदारों की जेब में चली जाती, जैसा कि पहले के शासनकाल में होता था।

65. मेरी सरकार शीघ्र ही सार्वजनिक क्रशर इकाइयाँ खोलने की प्रक्रिया में है जहाँ क्रशड रेत और बजरी नियंत्रित दरों पर बेची जाएगी।

66. मेरी सरकार शहरी सेवाओं के निरंतर और तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आवास और शहरी मामला मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण, 2023 में पंजाब को उत्तरी क्षेत्र में प्रथम रैंक दिया गया है।

67. मेरी सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

शहरी स्थानीय निकायों में 450 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के अलावा यूएलबी के पास उपलब्ध नगरपालिका फ़ंड के माध्यम से विकास कार्य शुरू किए हैं।

68. नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास में, मेरी सरकार ने 839.79 करोड़ रुपये की लागत से नए एसटीपी स्थापित करने और मौजूदा एसटीपी की कुल क्षमता 703 एमएलडी तक बढ़ाकर लुधियाना में बुड्ढा दरिया का कायाकल्प किया है। इसके परिणामस्वरूप सतलुज नदी में प्रदूषण कम होगा और नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के तटीय अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।

69. इसके अलावा, घटते भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, पेयजल स्रोत को भूजल से नहरी पानी में बदलने के लिए एक आदर्श बदलाव अपनाया गया है। मेरी सरकार ने अमृतसर शहर में 650 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है और जालंधर और पटियाला में 850 करोड़ रुपये से अधिक की नहर जल आधारित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसी प्रकार, लुधियाना में 1300 करोड़ रुपये की एक बड़ी नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा, राज्य के 87 कस्बों में लगभग 550 एमएलडी क्षमता के 87 जल उपचार प्लांट (डब्ल्यूटीपी) लगाए जा रहे हैं।

70. मेरी सरकार नागरिक अनुकूल और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनेक केन्द्रीकृत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। पंजाब में कम जोखिम वाले आवासीय भवनों के लिए मंज़ूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नई स्व-प्रमाणन योजना शुरू की गई है जो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जाने के बजाय योग्य पेशेवरों को इन भवनों के लिए भवन योजनाओं को मंजूरी देने की अनुमति देती है।

71. मेरी सरकार ने निम्न-मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराने के लिए किफायती आवास नीति अधिसूचित की है। इसी प्रकार, नगरपालिका सीमा, शहरी संपदा और औद्योगिक फोकल प्वाइंट के बाहर आने वाली और बिना अनुमति के या स्वीकृत योजनाओं से विचलन वाली इमारतों को राहत देने के लिए, मेरी सरकार ने इन्हें उचित दरों पर विनियमित करने के लिए एक नीति जारी की है।

72. मेरी सरकार ने भवन निर्माण योजना और लाइसेंस की मंजूरी के साथ भूमि उपयोग परिवर्तन जारी करने की अनुमति को विलय कर के ईज़ आफ़ डुइंग बिज़नेस की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाणपत्रों, पूर्णता प्रमाणपत्र, लेआउट और भवन योजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने

विकेंद्रीकृत विनियामक मंजूरी दी है, जो शहरी विकास प्राधिकरणों को विनियामक मंजूरी देने के लिए सशक्त बनाती है।

73. औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक अन्य कदम में, मेरी सरकार ने भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने और एमसी सीमा के बाहर, स्टैंडअलोन उद्योगों की कंपाउंडिंग सहित स्टैंडअलोन उद्योगों के समापन प्रमाण पत्र देने की शक्तियों को फैक्ट्री निदेशक को विकेंद्रीकृत कर दिया है। अब उद्योगपतियों को अपनी फैक्टरियों के बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दिलाने के लिए दो अलग-अलग विभागों (एच एंड यूडी और फैक्टरी) में आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

74. मेरी सरकार मोहाली शहर को अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित विश्व स्तरीय सुविधाओं और बुनियादी ढांचे वाले एक भविष्य के शहर के रूप में विकसित करने की इच्छा रखती है। राज्य द्वारा मोहाली को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया जा रहा है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए, गमाडा ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आईटी सिटी विकसित की है, जहां से कई उद्योग संचालित हो रहे हैं। भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए गमाडा सेक्टर 101 को औद्योगिक एस्टेट के रूप में विकसित करेगा, जहां कई उद्योग लगाए जाएंगे।

75. मेरी सरकार संकटग्रस्त लोगों के हितों के प्रति सदैव अत्यंत संवेदनशील रही है। जुलाई, 2023 के महीने के दौरान, राज्य को अत्याधिक बारिश के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ा। परंतु, मेरी सरकार राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की गई। बाढ़ के दौरान उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्हें जान-माल की हानि, पशुधन, मकान क्षति और फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया गया। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति के कारण पीड़ित लोगों की परेशानी को कम करने के लिए राज्य ने तुरंत मुआवजा जारी किया। पानी का बहाव कम होने पर मेरी सरकार ने तुरंत क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया।

76. मेरी सरकार ने नई तहसीलों/उप-तहसीलों परिसरों के निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार की प्राथमिकता हमेशा तहसीलों और उप-तहसीलों में आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना रही है जो सरकार के साथ लोगों का मुख्य संपर्क हैं। मेरी सरकार ने पंजाब के लोगों को विभिन्न देशों से प्राप्त दस्तावेजों की एम्बासिंग की ऑनलाइन सेवा की सुविधा प्रदान की है और 06.07.2023 को इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है।

77. मेरी सरकार ने पंजाब के लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए जिला पटवारी/कानूनगो कैडर को राज्यव्यापी कैडर में

समेकित किया है। इस पहल का उद्देश्य हर जिले में पर्याप्त पटवारियों की उपस्थिति की गारंटी देना, उनकी पोस्टिंग को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक परेशानी मुक्त ढंग से राजस्व सेवाएं पहुंचे।

78. मेरी सरकार ने गेहूं और धान की खरीद का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया है। 185 लाख टन धान और 130 लाख टन गेहूं निर्बाध रूप से खरीदा गया और किसानों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों सीज़न के लिए कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) रिकॉर्ड समय में प्राप्त हुई और खरीद के पहले दिन से ही किसानों को भुगतान शुरू हो गया, यह एक ऐसी उपलब्धि है जो पहले की सरकारों में कभी नहीं हुई थी।

79. मेरी सरकार ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की खरीद, वितरण और स्वीकृति के मापदंडों में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से राज्य में राइस शेलर उद्योग को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की है।

80. मेरी सरकार पंजाब में विशाल सड़क नेटवर्क बिछाने और उसे सुचारु रूप से चालू रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। चालू वित्तीय वर्ष के तहत 740 किलोमीटर की नई प्लान सड़कों के निर्माण पर 570 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

81. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है जिसमें ग्यारह (11) नंबर पैकेज पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेरी सरकार भूमि अधिग्रहण और परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग दे रही है। ग्यारह (11) पैकेजों में से दस (10) पैकेजों के लिए, नियत तारीखें घोषित कर दी गई हैं और एनएचएआई द्वारा इन पर सुचारू रूप से काम किया जा रहा है।

82. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लिंक रोड योजना के लिए, 836 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क लंबाई पूरी की गई है और 106 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

83. मेरी सरकार ने पंजाब के निवासियों को 3 टियर एसी ट्रेन और एसी बसों में देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों तक निःशुल्क ले जाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अधिसूचित की है। एक धार्मिक देश होने के नाते भारत के लोगों के लिए तीर्थयात्राएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन स्थानों से लोगों की धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। पंजाब राज्य में ऐसे कई बुजुर्ग हैं, जो अलग-अलग उम्र और आर्थिक साधनों की कमी के कारण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा प्रदेश के हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ स्थलों के दर्शन अवश्य करे। मेरी सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के

लिए आरामदायक रहने, भोजन, स्थानीय यात्रा और स्वागत किट की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार ने श्री हजूर साहिब, नांदेड़, पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ के लिए ट्रेनें चलाने के लिए आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल एक ट्रेन उपलब्ध करवाई गई थी जिससे 1000 लोग तीर्थयात्रा के लिए श्री हजूर साहिब गए और उसके बाद आईआरसीटीसी द्वारा कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई गई। मेरी सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए ट्रेनों के अलावा एसी बसों से भी पंजाब और आसपास के राज्यों में धार्मिक स्थलों की यात्रा की व्यवस्था की। तीर्थ यात्रा वाले धार्मिक स्थान श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंद पुर साहिब, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, माता वैष्णो देवी जी, माता ज्वाला जी, माता चिंतपूर्णी जी, माता नैना देवी जी, खाटू शाम जी और सालासर बालाजी धाम के दर्शन करवाएं हैं। हर दिन पंजाब के विभिन्न हिस्सों से 10 बसें तीर्थयात्रियों को उपरोक्त धार्मिक स्थलों तक ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं। 25.02.2024 तक कुल 25577 तीर्थयात्रियों को लेकर 602 बसें विभिन्न तीर्थस्थलों पर भेजी जा चुकी हैं।

84. मेरी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए लगभग सभी सेवाएं वाहन और सारथी वेब एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी हैं। वाहन निरीक्षण और फिटनेस मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा

मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है, जो वीएएचएएन वेब एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है।

85. वीवीएमपी (वलंटरी व्हीकल मार्डनाइज़ेशन प्रोग्राम) के तहत, मेरी सरकार ने लुधियाना और मोरिंडा में दो-दो वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को कार्यशील बनाया है। उपरोक्त सुविधाओं पर स्क्रैप किया गया वाहन नए वाहन खरीदने पर कर छूट का हकदार होगा।

86. मेरी सरकार ने मालेरकोटला जिले के टोलेवाल में एक क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है जो वर्तमान में हेवी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिफ्रेशर कोर्स की पेशकश कर रहा है और जिसे बाद में पूर्ण विकसित भारी वाहन लाइसेंस परीक्षण ट्रैक में अपग्रेड किया जाएगा।

87. पिछले वर्षों की तरह, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय पूल में धान में 21.40% और गेहूं में 46.24% की सीमा तक राज्य के लगातार योगदान को मान्यता देते हुए, मेरी सरकार ने अन्य फसलों में भी इसी तरह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहल की है। राज्य में फसलों के विविधीकरण का फोकस उन वैकल्पिक फसलों पर केंद्रित है जिन में कम पानी का उपयोग होता है। मेरी सरकार ने पंजाब के कपास क्षेत्र में कपास की बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 87,000 किसानों को कपास के बीज पर 17.13 करोड़ रुपये की 33% सब्सिडी प्रदान की है।

88. मेरी सरकार चावल की फसल की सीधी बुआई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1500/- रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसी योजना के तहत, वर्ष 2023-24 के दौरान, 75 करोड़ रुपये की बजटीय सब्सिडी राशि के साथ 19,097 किसानों द्वारा लगभग 1,70,000 एकड़ भूमि को कवर किया गया है।

89. बासमती की फसल को किसानों के लिए लाभकारी और आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए, मेरी सरकार ने एपीईडीए (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के समन्वय से एक बासमती विस्तार-अनुसंधान केंद्र और एक अवशेष परीक्षण लैबार्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे पंजाब के बासमती निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इस का सीधा लाभ किसानों को होगा। यह बासमती अवशेष परीक्षण लैबार्टरी जालंधर में स्थापित की जाएगी। बासमती की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसान मित्र और पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया जाता है। बासमती का रकबा 2022 के ख़रीफ़ में 4.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023 के ख़रीफ़ में 5.96 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का बासमती निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए, मेरी सरकार ने राज्य में 10 कृषि कीटनाशकों के

प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बासमती फसलों में कीटनाशक अवशेषों की समस्या को रोकने में बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं।

90. मेरी सरकार राज्य में फसल अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए मशीनरी की खरीद के लिए किसान समूहों/पंचायतों को 80% सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पराली प्रबंधन के लिए कुल 1,17,000 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत किसानों को लगभग 23,000 मशीनें प्रदान की गई हैं और इसी तरह आगामी वित्तीय वर्ष में भी यह योजना जारी रहेगी। मेरी सरकार क्मप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के विकास पर भी सक्रियता से काम कर रही है, जो प्रति वर्ष 1.87 मिलियन टन अधिशेष धान की पराली का उपयोग करेगी। इस तरह के उपायों से पिछले ख़रीफ़ कटाई सीज़न के दौरान आग की घटनाएं पिछले सीज़न में 49,922 से घटकर 36,623 हो गईं, जो कि इस सीज़न 26% है।

91. किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील होने के नाते, मेरी सरकार गन्ना उत्पादकों का पिछला बकाया चुकाने के साथ-साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी सक्रिय रही है।

पेराई वर्ष 2022-23 के दौरान, पंजाब में चीनी मिलों ने 30.11.2023 तक किसानों को 2572 करोड़ रुपये में से कुल 2558 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें निजी चीनी मिलों ने किसानों को 1846 करोड़ रुपये में से 1831 करोड़ रुपये का भुगतान किया तथा शेष 14 करोड़ रूपये के भुगतान हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। पंजाब की सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों को 725 करोड़ रुपये की पूरी बकाया राशि जारी कर दी गई है।

92. अपनी बात पर कायम रहते हुए, मेरी सरकार राज्य में कृषि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए किसानों के साथ बातचीत करने के लिए सरकार-किसान मिलनी का आयोजन कर रही है।

93. मेरी सरकार ने वर्तमान बटाला चीनी मिल के भीतर 3500 टीसीडी क्षमता के साथ 14 मेगावाट को-जेन प्लांट के साथ एक नया चीनी प्लांट स्थापित किया है, जिसके मार्च-2024 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और मौजूदा गुरदासपुर चीनी मिल में एक नया चीनी प्लांट (28 मेगावाट को-जेन प्लांट के साथ 5000 टीसीएस क्षमता) स्थापित किया जा रहा है और इस के मार्च-2024 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

94. मेरी सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये की लागत से मार्कफेड के तहत गोदामों की कवर क्षमता 75,000 मीट्रिक टन की है। राज्य के कारीगरों के उत्थान के लिए मेरी सरकार ने मिशन फुलकारी के नाम से एक परियोजना शुरू की है, जिसमें ग्रामीण स्तर के कारीगरों को नवीनतम शिल्प कौशल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

95. फरवरी, 2023 से अप्रैल, 2023 तक एक अभियान मोड में राज्य की 100% मवेशियों को लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) वैक्सीन की 25 लाख खुराकें निःशुल्क दी गईं। चालू वर्ष के दौरान, राज्य की 100% मवेशियों को दोबारा एलएसडी टीका मुफ्त में लगाया जाएगा।

96. पिछले एक वर्ष में उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली मादा बछिया पैदा करने के लिए सेक्सड सीमन की 1,30,000 खुराकें खरीदी गई हैं। इससे प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान में काफी मदद मिलेगी।

97. मेरी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास के रूप में मछली और झींगा पालन परियोजनाएं शुरू करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी दे रही है और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए डेयरी इकाइयां स्थापित करने में मदद कर रही है।

98. राज्य के वित्त को मज़बूत करने और भविष्य में ऋण प्रतिबद्धताओं के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधान रखने के लिए, मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) में 1750 करोड़ रुपये का योगदान डाला है, जिससे संचयी योगदान 7738 करोड़ रुपये हो गया है।

99. मेरी सरकार पिछले दो वर्षों में अपने ठोस प्रयासों के माध्यम से स्वयं-कर राजस्व में दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने में सक्षम रही है, अर्थात स्वयं-कर राजस्व में 21% की वृद्धि; राज्य जीएसटी में 16% की वृद्धि; वैट प्राप्तियों में 13% की वृद्धि और राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर करों में क्रमशः 11% की वृद्धि हुई है। (नवंबर, 2023 तक) जो उसके प्रभावी प्रयासों और उपलब्धि का संकेत है,

100. पंजाब बिल्डिंग फिस्कल एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिलिएंस फॉर ग्रोथ (बीफ़ेयर प्रोजेक्ट) के तहत, मेरी सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की पहल की है।

101. पंजाब राज्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, हमारे वित्त विभाग ने अपना स्वयं का आईएफएमएस बनाया है और ई-वाउचर, ई-मंजूरी, नान-ट्रेजरी अकाउंटिंग मॉड्यूल इत्यादि जैसे विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने पर काम कर

रहा है। इसके कार्यान्वयन से भुगतान प्रणाली अधिक मजबूत, पारदर्शी और कागज रहित हो जाएगी। पेंशन मामलों को समय पर प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए, पेंशन मॉड्यूल को पूरे पंजाब में लाइव कर दिया गया है, जिससे मैन्युअल प्रोसेसिंग के कारण होने वाली अत्यधिक देरी को दूर किया जा सके। इसके अलावा, ओल्ड पेंशनर डेटाबेस मॉड्यूल और मेडिकल रीइंबर्समेंट मॉड्यूल भी पंजाब में लागू किए जाने के लिए तैयार हैं।

102. मेरी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क और कराधान के राजस्व संग्रह में अच्छा उछाल देखा है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जनवरी 2024 तक जीएसटी 15.77% बढ़कर 15003 करोड़ रुपये से 17,369 करोड़ रुपये हो गई है; वैट 10.89% बढ़कर 5319 करोड़ रुपये से 5,898 करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क राजस्व 9.99% बढ़कर 6701 करोड़ रुपये से 7370 करोड़ रुपये हो गया है। एकत्रित किया जा रहा कुल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में जनवरी 2024 तक 27342 करोड़ रुपये से 13.44% बढ़कर 31018 करोड़ रुपये हो गया है।

103. मेरी सरकार ने राजस्व संग्रह में सुधार और कर चोरी रोकने के लिए जीएसटी डेटा के बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए आईआईटी हैदराबाद को नियुक्त किया है।

104. पुराने मामलों के अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार और उद्योग को जीएसटी के तहत उनके अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, मेरी सरकार ने 15 नवंबर, 2023 से वैट के तहत एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना शुरू की है जो 15 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी।

105. मेरी सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने और किसी भी खरीदारी के लिए बिल मांगने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए "बिल लियाओ इनाम पाओ" योजना भी लागू की है। जनवरी 2024 तक उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 59,000 बिल अपलोड किए जा चुके हैं और वे अब तक 54 लाख रुपये के पुरस्कार जीत चुके हैं।

106. मुझे यह खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने विधानसभा को डिजिटल रूप से काम करने और इसकी दक्षता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद की है। इससे विधानसभा के माननीय सदस्यों को भी अपना काम आसानी से और बिना किसी कागज के कर सकेंगे।

प्रिय सदस्यों, मेरी सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की उचित, निष्पक्ष और प्रभावी प्रदानगी सुनिश्चित करके पंजाब के लोगों से किए गए अपने वादे और प्रतिबद्धताएं पूरी की हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इस प्रतिष्ठित सदन में जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। मैं पंजाब के समग्र विकास के लिए जन-केंद्रित निर्णयों में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द !